मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3187
7 **अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड

3187. **श्रीमती हेमा मालिनीः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या शहरी अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए एक स्थायी मॉडल प्रदान करने वाले ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के तहत भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक नया अध्याय जोड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर द्वारा देश के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड का सफलतापूर्वक जारी होना स्थायी अवसंरचना और शहरी रेज़िलियंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की देशभर के भविष्य के शहरों के लिए राजकोषीय अनुशासन को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ जोड़ने का एक मॉडल बनने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यूएलबी को प्रोत्साहित करने हेतु, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 के अंतर्गत म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए 13 करोड़ प्रति 100 करोड़ रु. के बॉन्ड की दर से प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है, जो प्रति यूएलबी अधिकतम 26 करोड़ रु. के प्रोत्साहन के अधीन है। केवल ग्रीन बांड जारी करने के लिए दूसरी बार प्रोत्साहन भी यू.एल.बी को उपलब्ध है, जिसमें जारी किए गए प्रत्येक 100 करोड़ रु. के बॉन्ड पर 10 करोड़ रु. प्रोत्साहन की दर है, जो अधिकतम 20 करोड़ रु. तक है। अब तक 18 यूएलबी, अर्थात् आगरा, अहमदाबाद, अमरावती, भोपाल, चेन्नई, गांधीनगर, गाजियाबाद,

हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, राजकोट, प्रयागराज, पुणे, सूरत, वडोदरा, वाराणसी, विशाखापत्तनम और पिंपरी-चिंचवाड़, द्वारा शहरी अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड/ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से कुल 5,359 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। अहमदाबाद, गाजियाबाद, इंदौर, पिंपरी-चिंचवाड़ और वडोदरा द्वारा जारी ग्रीन बांड सहित कुल 377.33 करोड़ रुपये प्रोत्साहन के रूप में जारी किए गए हैं।

ख) गाजियाबाद नगर निगम (जीएमसी) ने 150 करोड़ रुपये का ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, जिसके लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 19.5 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन जारी किया है। इस बॉन्ड का सफलतापूर्वक जारी होना, नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने, क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने और पूंजी बाजार तक पहुँच बनाने के लिए गाजियाबाद नगर निगम की तत्परता को दर्शाता है।.

(ग) ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जलवायु-संरेखित वित्तपोषण तक पहुंच को सुगम बनाते हुए और राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देते हुए शहरों के लिए एक व्यावहारिक मॉडल के रूप में उभर रहे हैं। इनको जारी करने की संरचित और पारदर्शी प्रक्रिया सतत शहरी सेवाओं में सहायता करती है।

*****